

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन

आई.ए.एस.

अपील संख्या 22/2019

रामकरण पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 03.04.2019 न्यायालय तहसीलदार चिडावा, मुकदमा न0 39/2018  
प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामकरण अ0धा0 91 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित:-

1. श्री नेकीराम बुडानिया -एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी - राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.07.2019

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 03.04.2019 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैं:- निर्णय अदालत मातहत विरुद्ध कानून एवं पत्रावली होने से काबिले निरस्त है। अदालत मातहत ने महज कयासत पर आधारित होकर निर्णय पारित करने में गलती कानून की है। अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आधारित होकर निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अपीलान्त को जबाब देही व दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होकर निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान नहीं रिकार्ड नहीं किये। मात्र राजनैतिक द्वेषता एवं हल्का पटवारी से झूठी रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्त को बेदखल करने में गलती कानूनी की है। अपीलान्त ने गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 718 कुल रकबा 0.14 हैक्टर भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना तो पूर्व में कभी किया तथा ना ही वर्तमान में किया गया है बल्कि वास्तविकता यह कि उक्त रास्ता वर्तमान में भी चालू है। इस तरह वास्तविक जांच के अभाव में महज पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट पर विश्वास कर अपीलान्त

  
जिला कलेक्टर झुंझुनू

की बेदखली करने में गलती कानूनी की है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर निर्णय मातहत अदालत दिनांक 03.04.2019 निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्त के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध है क्योंकि अदालत मातहत ने महज कयासत पर आधारित होकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आधारित होकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त को जबाब देही व दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान नहीं रिकार्ड नहीं किये। मात्र राजनैतिक द्वेषता एवं हल्का पटवारी से झूठी रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्त को बेदखल करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्त ने गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 718 कुल रकबा 0.14 हैक्टर भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना तो पूर्व में कभी किया तथा ना ही वर्तमान मकिया गया है बल्कि वास्तविकता यह कि उक्त रास्ता वर्तमान में भी चालू है। इस तरह वास्तविक जांच के अभाव में महज पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट पर विश्वास कर अपीलान्त की बेदखली आदेश पारित किये हैं। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर निर्णय मातहत अदालत दिनांक 03.04.2019 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्त ने दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्त को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये हैं। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत द्वारा उक्त विवादित प्रकरण में ग्राम बुडानिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 718 कुल रकबा 0.14 हैक्टर गै0मु0 रास्ता की भूमि है। अपीलान्त का कथन है कि अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं किया परन्तु रिकार्ड मातहत के अवलोकन से साफ जाहिर है कि अपीलान्त की तलबी दिनांक 27.08.2018 को विधि सम्मत रूप से हुई है जिसे अपीलान्त ने स्वयं प्राप्त किया है। अदालत मातहत द्वारा सुनवाई हेतु काफी अवसर प्रदान किये परन्तु अपीलान्त न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर आदेश पारित किया है। प्रकरण में अपीलान्त द्वारा किये गये अतिक्रमण की भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि है जो कि राजकीय भूमि है जिस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण वैध नहीं माना जा सकता। न्यायालय की दृष्टि में अपील अपीलान्त में कोई फोर्स नहीं है। अतः अदालत मातहत के निर्णय की पुष्टि करते हुये अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)

जिला कलेक्टर झुंझुनू  
जिला कलेक्टर झुंझुनू